Sale of defence vehicles to civilians

*659. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SIHUKANT RAMCHANDRA JICHKAR;

Will the PRIME MINISTER be plea-sed to state:

(a) what is the total number of defence vehicles sold to civilians during the last three years;

(b) what is their total vahw; and

(c) what is the criteria on defence vehicles are discarded from Defeace use and made available for sale to civilians?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b)

Year	Number of vehicles sold	Amount realised (Rs. in Crores)
1991	8618	25.89
1992	9837	33.59
1993	12905	44.33

Since these vehicles have been disposed of from a large number of depots/ points, the book value totals of all these vehicles have not been compiled.

(c) A defence vehicle becomes due for sauird either if it has run the prescribed kilometrage for that category of vehicles or has been in me for the prescribed somber of years, whichever is later, or has met with a accident and has been declared as being 'Beyond Economical Repair*.

लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् द्वारा गुजरात को वित्तीय सहायता दिया जाना

*660. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कापार्ट (लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद्) के माध्यम से किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी किन-किन संस्थाओं के कार्यकरण की यह देखने के लिए समीक्षा की गई है कि धन का समुचित ढंग से उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ; और

(ग) किन-किन संस्थाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) गुजरात में लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, सहायता किए गए गैर-सरकारी संगठनों की संख्या, स्वीकृत राशि तथा रिलीज की गई राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए) ।

कापार्ट (लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद), स्वयंसेवी संगठनों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करता हैं ताकि परियोजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके । परिषद ने निगरानी-कर्त्ताओं के रूप में अनेक अनुभवी लोगों का पैनल बनाया है । परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने के पश्चात् निधियां उपर्युक्त